



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]
No. 129]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2003/फाल्गुन 27, 1924
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2003/PHALGUNA 27, 1924

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2003

सा.का.नि 227(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 194

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 2003

राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 36, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 41 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 40 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं० 3 आदेश, 2003 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 कर 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 1 नवंबर, 2000 के ठीक पूर्व यथाविद्यमान मध्य प्रदेश, 9 नवंबर, 2000 के ठीक पूर्व यथाविद्यमान उत्तर प्रदेश और 15 नवंबर, 2000 के ठीक पूर्व यथाविद्यमान बिहार राज्यों के लिए सिफारिश किए गए विपत्ति राहत निधि के अंश को, संबंधित उत्तरवर्ती राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, तथा बिहार और झारखंड के बीच अंतर अनुसचिवीय समिति की सिफारिशों के आधार पर और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अनुसरण में उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा दखलकृत राज्यक्षेत्रों के क्षेत्र के अनुपात में अवधारित किया गया है। विपत्ति राहत निधि के केन्द्र और राज्यों के अंशों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच प्रभाजित किया गया है और इसका यह अर्थ लगाया जाएगा कि उन्हें नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में क्रमशः 308.26:135.19, 241.07:53.34 और 94.16:79.72 के अनुपात में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, तथा बिहार और झारखंड राज्यों के बीच प्रभाजित किया गया है:

सारणी

राज्य	केन्द्र के और राज्यों के अंश की प्रतिशतता	2000-01	2001- 02	2002-03	2003-04	2004-05	कुल 2000-05
				(रुपए लाख में)			
मध्य प्रदेश	75% और 25% कुल	4698 1566 6264	4932 1644 6576	5178 1726 6904	5439 1812 7251	5710 1903 7613	25957 8651 34608
छत्तीसगढ़	75% और 25% कुल	2060 687 2747	2163 721 2884	2272 757 3029	2385 795 3180	2503 835 3338	11383 3795 15178
उत्तर प्रदेश	75% और 25% कुल	10970 3657 14627	11519 3840 15359	12095 4032 16127	12700 4233 16933	13336 4445 17781	60620 20207 80827
उत्तरांचल	75% और 25% कुल	2428 809 3237	2549 849 3398	2676 892 3568	2810 937 3747	2950 984 3934	13413 4471 17884
बिहार	75% और 25% कुल	5022 1674 6696	5273 1758 7031	5537 1845 7382	5814 1938 7752	6105 2035 8140	27751 9250 37001
झारखंड	75% और 25% कुल	4252 1417 5669	4465 1488 5953	4688 1563 6251	4922 1641 6563	5168 1723 6891	23495 7832 31327

4. विपत्ति राहत निधि को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र सं. 43(1)पी.एफ-1/2000 तारीख 24 नवंबर, 2000 द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों में अधिकथित शर्तों के पूरा करने पर राज्यों को निर्मुक्त किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई रकमों को राष्ट्रपतीय आदेश जारी करके वित्तीय वर्ष के अंत में नियमित किया जाएगा।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।”

[फा. सं. 19(3)/03/एल आई]
सुभाष सी. जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th March, 2003

G.S.R. 227(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 194**THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 3
ORDER, 2003**

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, read with section 36 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000), section 41 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000) and section 40 of the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), the President hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2003.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. The shares of the Calamity Relief Fund, recommended by the Eleventh Finance Commission for the States of Madhya Pradesh as it existed immediately before the 1st November, 2000, Uttar Pradesh as it existed immediately before the 9th November, 2000 and Bihar as it existed immediately before the 15th November, 2000, has been determined between the respective successor States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Uttaranchal, and Bihar and Jharkhand in the ratio of the area of the territories occupied by the successor States, on the basis of the recommendations of Inter-Ministerial Committee and in pursuance of the provisions of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 and the Bihar Reorganisation Act, 2000. The Centre's and the States shares of the Calamity Relief Fund have been apportioned between the successor States and shall be construed to be apportioned between the States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Uttaranchal, and Bihar and Jharkhand in the proportion of 308.26 : 135.19, 241.07 : 53.34 and 94.16 : 79.72 respectively as specified in the table below:

TABLE

State	Percentage of Centre's and State's share	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	Total (2000-05)
Rupees in lakhs							
Madhya Pradesh	75% and 25%	4698	4932	5178	5439	5710	25957
	Total	1566	1644	1726	1812	1903	8651
		6264	6576	6904	7251	7613	34608
Chhattisgarh	75% and 25%	2060	2163	2272	2385	2503	11383
	Total	687	721	757	795	835	3795
		2747	2884	3029	3180	3338	15178
Uttar Pradesh	75% and 25%	10970	11519	12095	12700	13336	60620
	Total	3657	3840	4032	4233	4445	20207
		14627	15359	16127	16933	17781	80827
Uttaranchal	75% and 25%	2428	2549	2676	2810	2950	13413
	Total	809	849	892	937	984	4471
		3237	3398	3568	3747	3934	17884
Bihar	75% and 25%	5022	5273	5537	5814	6105	27751
	Total	1674	1758	1845	1938	2035	9250
		6696	7031	7382	7752	8140	37001
Jharkhand	75% and 25%	4252	4465	4688	4922	5168	23495
	Total	1417	1488	1563	1641	1723	7832
		5669	5953	6251	6563	6891	31327

4. The Calamity Relief Fund will be released to States on fulfilment of the conditions laid down in the guidelines issued by the Ministry of Finance, Department of Expenditure vide letter No. 43 (1) PF-1/2000 dated the 24th November, 2000. The amounts released during each year shall be regularised through the issue of Presidential Order at the end of the financial year.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President."

[F. No. 19(3)/03/L]
SUBHASH C. JAIN, Secy.